राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 290

प्रगति

समाचार पत्र

जुलाई 2019

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

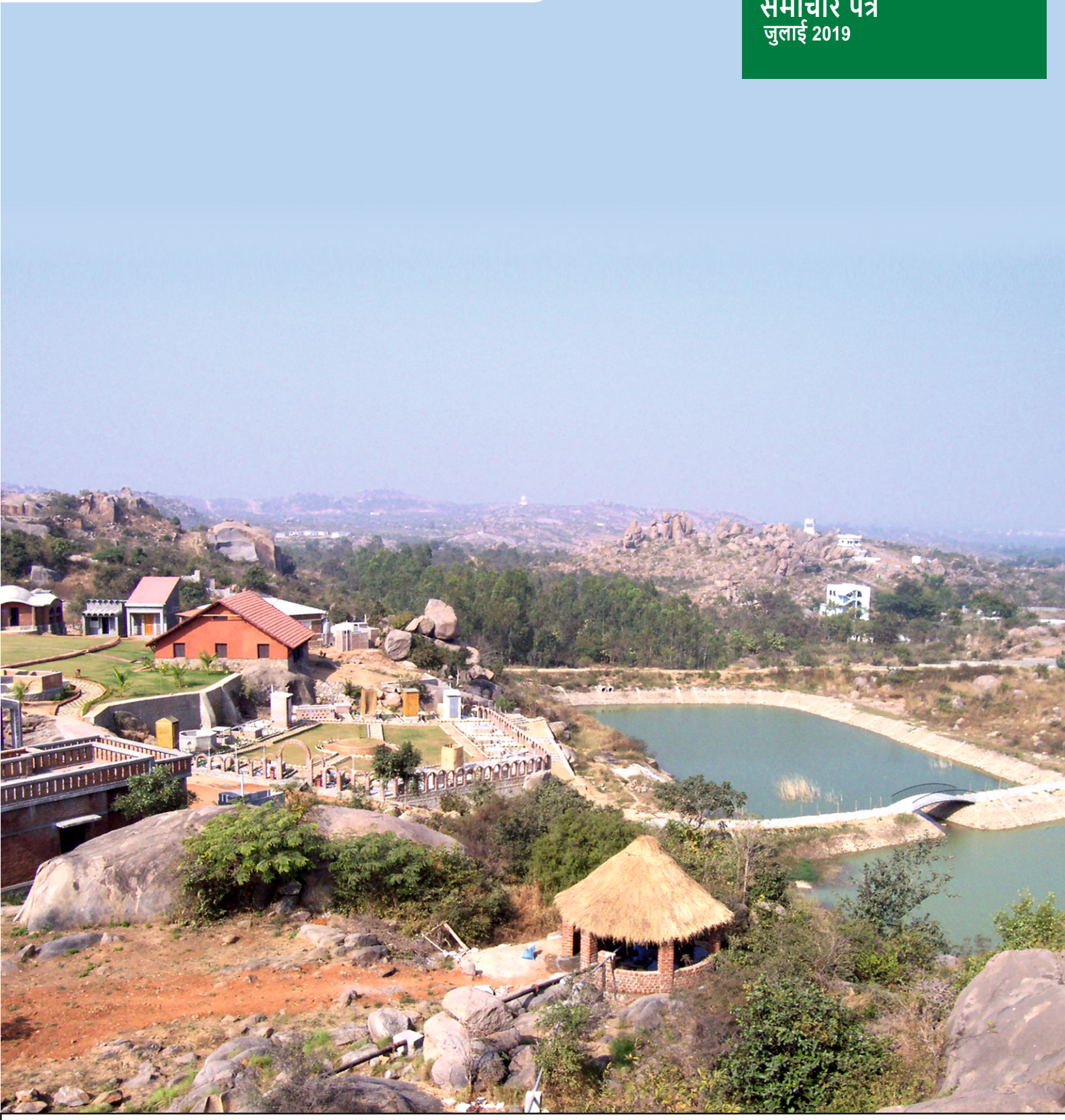

ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना: ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, एनआईआरडीपीआर के कार्य

3 ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना: ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, एनआईआरडीपीआर के कार्य

विषय-सूची

8

तेलंगाना को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए तेलंगाना में पोषण अभियान कार्यान्वयन पर अभिसरण बैठक

9

पशुधन के माध्यम से बेहतर आजीविका को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

9

पीएमजीएसवाई सड़क योजना और प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों पर पांच दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

10

सीएफआईई द्वारा वित्तीय साक्षरता पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

11

मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम

12

पीएमजीएसवाई सड़क योजना और प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

13

ग्रामीण विकास व्यवसायियों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण क्रियाविधि पर एनआईआरडीपीआर ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम

14

बेहतर सेवा वितरण के लिए ई-शासन की रणनीतियों पर क्षेत्रीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

15

एमजीएनआरईजीएस और डे–एनआरएलएम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम: सीबीओ की भागीदारी के साथ श्रम गतिशीलता और सामाजिक लेखापरीक्षा को बढ़ावा देना

16

कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में ऋण प्रबंधन पर बैंकरों के लिए कार्यक्रम

18

पुस्तकालय व्याख्यान: टेबल-नमक के अज्ञात खतरों का खुलासा

आरटीपी, एनआईआरडीपीआर का प्रवेश द्वार

ग्रामीण क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना: ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, एनआईआरडीपीआर के कार्य

राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की भूमिका को एक महत्वपूर्ण घटक माना जा रहा है । भारत में, 1958 में सरकार द्वारा प्रारंभ विज्ञान नीति ढांचे की शुरुआत के साथ विकासात्मक मुद्दों के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सक्रिय रूप से विचार किया गया । वर्षों से, इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं । इस दिशा में हाल ही में इस दशक की घोषणा नवप्रवर्तन दशक (2010- 2020) के रुप में की गई है ।

भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, 2013 को शुरू करके अपने विजन का और अधिक विस्तार किया हैं, जिसके परिणामस्वरूप यह लोगों में सामाजिक हितैषी और आर्थिक संपदा को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है । इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने के लिए, यह आवश्यक है कि अनुसंधान और विकास संस्थाएं सक्रिय रूप से मुद्दों की पहचान करने में कार्यरत रहे, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में लोगों के विकास को बढ़ावा देने और बेहतर उद्यमशीलता और आम आदमी की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विकसित वैज्ञानिक समाधानों का भी उपयोग करते हैं ।

ग्रामीण भारत में लोगों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, पर्यावरण, खाद्य, पोषण, जल, स्वच्छता, आवास और सस्ती स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में मुद्दों का समाधान करना एक बड़ी चुनौती है। अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वह बेरोजगारी का मुद्दा है । हाल के वर्षों में भारत की निरंतर औसत वृद्धि के बावजूद, पर्याप्त रोजगार सृजन क्षमता प्रदान करने के रास्ते आनुपातिक रूप से नहीं बढ़े हैं। ग्रामीण भारत में लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक विशेष फोकस के साथ उपयुक्त और टिकाऊ तकनीकों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास संस्थानों को शामिल करके इन महत्वपूर्ण मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सकता है । इसके साथ-साथ, रणनीतियों जैसे कौशल और क्षमताओं को उन्नत करना; सूक्ष्म उद्यम और स्वरोजगार का समर्थन करना; और बेरोजगारी की इन चुनौतियों से निपटने के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए नए मॉडल तैयार करने की तत्काल आवश्यकता है । इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) , हैदराबाद ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की स्थायी आजीविका और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए क्षमता निर्माण की पहल करने के लिए 2003 में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) की स्थापना की ।

" ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क के माध्यम से एनआईआरडीपीआर द्वारा उपयुक्त प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के प्रभाव को अच्छी तरह से पहचाना गया है और इसके विकास के साथ ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न हितधारकों द्वारा सराहना की गई है "

उपयुक्त प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में एनआईआरडीपीआर की पहल

क) ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क और प्रौद्योगिकी इकाईयाँ

इन उद्देश्यों की प्राप्ति में, आरटीपी में स्थापित विभिन्न प्रौद्योगिकी इकाइयों के माध्यम से उपयुक्त और सस्ती ग्रामीण प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला की पहचान की गई है और उन्हें बढ़ावा दिया गया है । इस उद्देश्य के लिए, एनआईआरडीपीआर ने इस उद्देश्य को साकार करने के लिए गतिशील प्रौद्योगिकी विकास

आरटीपी, एनआईआरडीपीआर का एक हवाई दृश्य

एजेंसियों, उद्यमियों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ एक अद्वितीय साझेदारी दृष्टिकोण विकसित किया है। इस महत्वपूर्ण गतिविधि के भाग के रूप में, एनआईआरडीपीआर संस्थानों द्वारा विकसित किए जा रहे उचित और परंपरागत से हटकर नवाचारों की पहचान कर रहा है, जिनका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लाभ के लिए उद्यमशीलता और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए 20 से अधिक प्रौद्योगिकी इकाइयां स्थापित की गई हैं, और कई संभावित एजेंसियों के साथ चर्चा की जा रही है। इसके अलावा, हाल ही में, वैशाली में कॅपार्ट के कैरियर-सह मार्गदर्शन केंद्र को आरटीपी, एनआईआरडीपीआर द्वारा लिया गया है और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

आरटीपी पर स्थापित एक अन्य महत्वपूर्ण इकाई राष्ट्रीय ग्रामीण भवन निर्माण केन्द्र (एनआरबीसी) है, जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए पारंपरिक और आधुनिक सामग्रियों और तकनीकों दोनों के सम्मिश्रण से लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण तकनीकों को एक साथ लाता है। इन संरचनाओं को मुख्य रूप से स्थानीय सामग्री और लोगों के कौशल का उपयोग करके बनाया गया है। इन संरचनाओं के निर्माण की लागत मिट्टी के प्रकार और सामग्रियों की स्थानीय उपलब्धता के आधार पर पारंपरिक निर्माण लागत की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कम है। इस केंद्र में प्रदर्शित 20 विभिन्न टाइपोलॉजी भवनों में 100 से अधिक तकनीकों को दर्शाया गया है।

प्रत्येक वर्ष, विभिन्न तकनीकों पर लगभग 3,000 लोगों को शामिल करने वाले लगभग 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस पहल ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में एसएचजी और युवाओं द्वारा उद्यमशीलता की गतिविधियों को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। उनके द्वारा शुरू की गई उद्यमशीलता की कुछ पहलों में गृह-आधारित उत्पादों, मशरूम की खेती, टिकाऊ आवास प्रौद्योगिकियों, मिट्टी के ब्लॉक बनाने, सौर उपकरण उत्पादन, पत्ती बनाने, शहद उत्पादन और प्रसंस्करण, वर्मीकम्पोस्टिंग, हस्तनिर्मित कागज, हर्बल उत्पादों का निर्माण शामिल हैं। नीम तेल और केक प्रसंस्करण, प्राकृतिक रंगाई, सोया और बाजरा प्रसंस्करण, सुगंधित तेल निष्कर्षण, आदि तथा इसके अलावा, आरटीपी भी नियमित रूप से ग्रामीण लोगों, अधिकारियों, कॉलेज और स्कूल के छात्रों के लिए कई प्रदर्शन सह अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करता है।

ख) ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेला

आरटीपी वर्ष 2003 से एनआईआरडीपीआर के स्थापना दिवस समारोह के एक भाग के रूप में ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेलों का आयोजन कर रहा है। इन वर्षों में, देश के विभिन्न भागों से कई ग्रामीण नवप्रवर्तनकर्ताओं, कारीगरों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और उद्यमियों ने उत्पादों की एक अद्भुत श्रृंखला का प्रदर्शन किया। प्रत्येक वर्ष, ग्रामीण नवप्रवर्तनकर्ताओं, स्वयं सहायता समूह, कारीगर, हथकरघा देश भर के बुनकर और ग्रामीण उद्यमी मेले में भाग लेते हैं। प्रदर्शित और बेचे जाने वाले उत्पादों में हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद, औषधीय और सुगंधित उत्पाद, चमड़े के सामान, लकड़ी के खिलौने, सजावटी सामान, संसाधित पारंपरिक खाद्य पदार्थ, कॉयर उत्पाद, लकड़ी पर नक्काशी, पीतल के बर्तन, जूट और कपड़ा उत्पाद, फैशन और आदिवासी गहने, सौर ऊर्जा आधारित अनुप्रयोग / उत्पाद आदि शामिल हैं, जो बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। मुख्य रूप से, उत्पादों की बिक्री और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए मेला आयोजित किया जाता है,

उद्यमिता, ग्रामीण प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के प्रचार प्रसार पर बाजार संबंध बनाने और ज्ञान के आदान-प्रदान की संभावना जो विभिन्न संगठनों / व्यक्तियों द्वारा विकसित किए जाते हैं जो एक स्थान पर लोगों के लिए उपयोगी होते हैं, और उपभोक्ताओं और उद्यमियों / प्रौद्योगिकीविदों के बीच जागरूकता और संबंध बनाते हैं।

परंपरा को जारी रखते हुए, 16 वें ग्रामीण प्रौद्योगिकी और शिल्प मेले का आयोजन 29 नवंबर से 3 दिसंबर, 2018 तक 'जन योजना: सतत विकास के लिए विकेंद्रीकृत रणनीति' विषय के रूप में किया गया। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे 20 राज्यों के प्रतिभागियों द्वारा 220 से अधिक स्टालों का प्रदर्शन किया गया। एक विशेष कार्यक्रम के रूप में, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा प्रायोजित 'राष्ट्रीय मछली महोत्सव' देश में मछली की खपत को लोकप्रिय बनाने और मछली के स्वास्थ्य लाभों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए आयोजित किया गया। मछली स्टालों में आगंतुकों के लिए विभिन्न विदेशी मछली व्यंजनों को परोसा गया। पांच दिनों तक चलने वाले इस मेले में 50,000 से अधिक लोग उपस्थित हुए। इस आयोजन को उद्यमियों, आगंतुकों और विभिन्न संस्थानों के अधिकारियों ने काफी सराहा। यहां तक कि इसकी भव्यता और बढ़ी सफलता के लिए देश भर में राज्य की राजधानियों में वार्षिक रुप से आयोजित बड़े सारस मेलों के साथ तुलना की जाती है।

ग) ग्रामीण इनोवेटर्स स्टार्ट-अप सम्मेलन

नवोन्मेषणों का कारण बनने वाले स्वर्गीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की याद में, एनआईआरडीपीआर ने नवाचारों को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास की दिशा में नवाचारों, स्टार्ट-अप / ग्रामीण प्रौद्योगिकियों में तेजी लाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और ग्रामीण नवोन्मेषकों के समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2017 में रूरल इनोवेटर्स स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव (आरआईएससी) की शुरुआत की है। यह आयोजन ग्रामीण नवोन्मेषकों और नवोदित स्टार्ट-अप के एक मंच के रूप में अपने उत्पादों, विचारों / प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने और मालिकों और निवेशकों के साथ जुड़ने के लिए कार्य करता है। इस घटना के माध्यम से, एनआईआरडीपीआर का उद्देश्य नवप्रवर्तकों / स्टार्ट-अप को उनके विकास, बढोत्तरी और उनके प्रौद्योगिकियों / नवाचारों के व्यवसायीकरण के लिए उपयुक्त संस्थानों, इनक्यूबेटरों, निवेशकों और वित्तीय संस्थानों से जोड़ना है। अच्छी और उत्साहजनक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, इसका आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। आरआईएससी का दूसरा संस्करण एनआईआरडीपीआर में 30 - 31 अगस्त, 2018 के दौरान दो दिनों के लिए आयोजित किया गया। नवप्रवर्तनकर्ताओं और स्टार्ट-अप के प्रदर्शन हेतु आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकय्या नायडू द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान 150 से अधिक स्टॉल लगाए गए। गणमान्य लोगों ने प्रतिभागियों के साथ उनकी तकनीकों के बारे में बातचीत की और ज्ञान के शब्दों के साथ उन्हें प्रोत्साहित किया।

आरआईएससी 2018 का आयोजन सात विषयों अर्थात् कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ, हरित ऊर्जा, अपशिष्ट से धन, सतत आवास, स्वास्थ्य और बुजुर्गों की देखभाल, पेयजल और स्वच्छता एवं सतत आजीविका पर किया गया। इसके अलावा, स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों और आम जनता के लिए रूरल इनोवेशन एंड डिजाइन (आरआईडीई) चैलेंज नामक एक सब-इवेंट का आयोजन किया गया ताकि आरआईएससी 2018 के लिए निर्दिष्ट विषयों पर ग्रामीण क्षेत्रों में सामना की जा रही समस्याओं के समाधान करने हेतु अवसर प्रदान किया जा सके।

इस कार्यक्रम में देश के 23 राज्यों के लगभग 300 इनोवेटर्स, स्टार्ट-अप और छात्रों ने भाग लिया, जिसमें 71 इनोवेशन, 30 स्टार्ट-अप शामिल थे और आरआईडीई चैलेंज के तहत 63 विचारों को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास सहयोग, भारतीय पैकेजिंग संस्थान और राष्ट्र लघु उद्योग सहयोग आदि जैसे प्रमुख सरकारी संस्थानों ने भी प्रतिभागियों के लाभ के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया। विभिन्न राज्यों के राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों और एमएस स्वामीनाथन फाउंडेशन ने देश भर के नवप्रवर्तनकर्ताओं और स्टार्ट-अप की पहचान करने के प्रयासों में सक्रिय रूप से जुडकर समर्थन दिए। नवोन्मेषकों, स्टार्ट-अप और छात्रों से प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर विचारों को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए एक कार्यवाही की गई है।

आरआईएससी आयोजन के प्रत्येक विषय के तहत नवप्रवर्तकों और स्टार्टअप के लिए पुरस्कार (संख्या में पूरी तरह से 14) क्रमशः रु 1.20 लाख और रु 2.40 लाख के बराबर प्रदान किए गए। आरआईडीई के प्रतिभागियों के लिए, तीन पुरस्कारों, अर्थात्, पहला - रु. 10,000, दूसरा - रु. 5,000 और तीसरा रु. 3,000- आरआईएससी आयोजन के सभी सात विषयों में प्रतिभागियों की प्रत्येक श्रेणी (यानी स्कूल के छात्रों, कॉलेज के छात्रों और आम जनता) के लिए प्रदान किए गए। इस आयोजन को देश में ग्रामीण नवाचारों को बढ़ावा

आरआईएससी-2018 के उद्घाटन के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकय्या नायुडू

देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। मंच के माध्यम से पहचाने जाने वाले कई नवप्रवर्तनकर्ताओं को पहचाना जा रहा है और इस आयोजन से प्राप्त समर्थन और मान्यता के परिणामस्वरूप उन्होंने अपने काम को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। इसके अलावा, समय-समय पर एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित विशेष कार्यशालाओं के माध्यम से पैकेजिंग, विपणन और डिजाइन पर एक्सपोजर प्रदान करने हेतु अंतिम सूचियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। आरआईएससी का तीसरा संस्करण अगस्त, 2019 के महीने में आयोजित किया जाएगा।

घ) संस्थागत सहयोग और संयुक्त कार्य

कई बार, विभिन्न संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियाँ संस्थानों की अलमारियों में ही रह जाती और जो प्रयोगशालाएँ हैं इनका विकास करता है वह उन लोगों तक नहीं पहुंचता है जो इसके अनुप्रयोगसे लाभान्वित हो सकते हैं। भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी), हैदराबाद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी), अहमदाबाद, आदि जैसे कुछ सरकारी संस्थानों की विशेषज्ञता बड़े उद्योगों के लिए उपलब्ध हैं और वही, यद्यपि ग्रामीण कारीगर, उद्यमियों, एसएचजी द्वारा विकसित / निर्मित उत्पादों के लिए अत्यधिक उपयुक्त और प्रासंगिक है, उक्त ग्रामीण उद्यमियों के लिए सुलभ नहीं हैं। एनआईआरडीपीआर, ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़ने और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के अपने जनादेश के साथ, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक नवाचारों / उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एस एण्ड टी संस्थानों के लिए एक मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कई बार, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान ग्रामीण परिदृश्य की सामाजिक गतिशीलता से सुसज्जित नहीं हो सकते हैं और निम्न स्तर पर इन प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग प्रासंगिकता, तकनीकी व्यवहार्यता, व्यावहारिक प्रयोज्यता और वित्तीय व्यवहार्यता जैसे मुद्दों के कारण नहीं हो रखते हैं, जिसके लिए एनआईआरडीपीआर प्रदर्शन और प्रतिक्रिया की सुविधा प्रदान कर सकता है ताकि नवाचारों / प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रचार हो।

इस दिशा में, हाल ही में एनआईआरडीपीआर ने देश भर में एसएचजी के उत्पादों की पैकेजिंग / लेबलिंग को बेहतर बनाने में विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ सहयोग किया। अब तक दो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और एसएचजी एवं ग्रामीण उद्यमियों के बीच कार्यक्रमों से उत्पन्न प्रभाव उत्कृष्ट रहा है। डीआरडीओ लैब्स, एनएफडीबी, सीआईटीडी, आदि जैसे सरकारी संस्थानों और उद्योगों के साथ सहयोग सहित पहल की जा रही है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय (पीएसए) और रुटैग-आईआईटी के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में हुई चर्चाओं में, यह महसूस किया गया कि देश के बड़े वैज्ञानिक समुदाय के साथ जुड़ाव, एनआईआरडीपीआर में पहले ही की गई पहलों के लिए अधिक तालमेल प्रदान कर सकता है। उपरोक्त के आधार पर, एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सीएसआईआर, डीएसटी, डीआरडीओ, आईआईटी रुटैग और अन्य आर एण्ड डी संस्थानों जैसे एस एण्ड टी संस्थानों के साथ परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। इसके अलावा, राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के साथ सहयोग से मत्स्य प्रौद्योगिकी विकास पर काम करने वाली संस्थाओं के साथ एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई।

ग्रामीण स्टार्ट-अप सम्मेलन -2018 में अपने नवाचार को प्रदर्शित करते हुए एक प्रतिभागी

परामर्श से उभरी कुछ सिफारिशें हैं:

- ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के लिए तकनीकी समाधान को बढ़ावा देने के लिए एस एण्ड टी संस्थानों के सहयोगी मंच की जरूरत है।

- एस एण्ड टी संस्थान आदर्श ग्राम विकास पहल प्रारंभ कर सकता हैं और जहां भी संभव हो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्रवाई अनुसंधान परियोजनाएं चला सकता हैं।

- प्रदर्शन और उद्यमिता संवर्धन के लिए रुटैग-आईआईटी द्वारा विकसित नवाचारों को बढ़ाने के लिए तंत्र विकसित करना ।

- सीएसआईआर, डीएसटी, डीआरडीओ इत्यादि जैसे संबंधित एस एण्ड टी संस्थानों द्वारा पहले से विकसित प्रौद्योगिकियां जिनकी बड़ी प्रभाव क्षमता है, को पहचाना और बढ़ावा दिया जा सकता है।

- एनआईआरडीपीआर या एस एण्ड टी संस्थान के परिसर में वार्षिक कैलेंडर आधार पर बाजार तैयार तकनीकें और परिपक्व पर उद्यमशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।

- ग्रामीण उद्यमियों के लिए प्रासंगिक सरकारी एस एण्ड टी संस्थानों द्वारा विकसित कुछ नई और उभरती हुई तकनीकों को प्रदर्शित करने के लिए एक 'वार्षिक एस एण्ड टी कॉन्क्लेव' का आयोजन।

- समाचार पत्र / ऑनलाइन वेबसाइट / सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रामीण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान प्रबंधन इकाई का निर्माण।

परामर्श और तकनीकी सहायता

आरटीपी उपयुक्त तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी निकायों और निजी संस्थाओं सहित विभिन्न ग्राहकों के लिए सक्रिय रूप से परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जिन क्षेत्रों में इस तरह की सेवाएं दी जाती हैं, उनमें से कुछ हैं: टिकाऊ आवास, मत्स्य विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, संरक्षण आदि। प्रौद्योगिकी साझेदार इकाइयों और प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों की मदद से आरटीपी द्वारा कई परियोजनाएँ संचालित की गई हैं । स्थायी गृह निर्माण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में की गई गतिविधियों में भवनों का डिजाइनिंग, मड ब्लॉक तैयारी और आपूर्ति, ऑन-साइट पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन, राजमिस्त्री और इंजीनियरों का प्रशिक्षण आदि शामिल हैं। निष्पादित किए गए कुछ उल्लेखनीय कार्यों में छत्तीसगढ़ में मेडिकल उप-केंद्र का निर्माण, पोलावरम बांध परियोजना द्वारा विस्थापित परिवारों के लिए घरों का डिजाइन, नाटको फाउंडेशन के लिए आदर्श आंगनवाड़ियों का डिजाइन और निर्माण, प्रगति रिसॉर्ट के लिए मिट्टी ब्लॉक निर्माण परियोजना का परीक्षण और स्थापना, तकनीकी सहायता और हैदराबाद में कई शहरी आवासों के लिए मिट्टी ब्लॉकों की आपूर्ति, आदि शामिल है।

मत्स्य क्षेत्र में, ईको हैचरी स्थापित करना आइस ब्लॉक मेकिंग मशीन, डिबोनिंग मशीन, सोलर रेफ्रीजिरेटर और शुष्क मछली के लिए डिहाइड्रेटर की आपूर्ति जैसी परियोजनाएं, की जा रही है। जिन एजेंसियों ने सेवाओं का लाभ उठाया है उनमें राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड, पश्चिम बंगाल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, पश्चिम बंगाल राज्य सहकारिता, पंजाब और तेलंगाना राज्य मत्स्य विभाग आदि शामिल है । नवीकरणीय ऊर्जा के बाद पवन, सौर, जैव-गैस, आदि से संबंधित परियोजनाओं को प्रारंभ किया जा रहा है । उल्लेखनीय कार्यों में लक्षद्वीप में मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर हाइब्रिड पवन एवं सौर मिलों की स्थापना, झारखंड में हाइब्रिड सौर एवं पवन मिलों के साथ पिंजरा की संस्कृति की स्थापना, भुवनेश्वर में हैचरी के लिए सौर प्रकाश समाधान, तेलंगाना के स्कूलों में सौर प्रकाश और शीतलन प्रणाली आदि शामिल हैं।

नवोदित उद्यमियों के बड़ी संख्या को सलाह देने के लिए सफल उद्यमियों को प्रेरित करने का यह अनूठा तरीका कई आधारों पर एक पथप्रदर्शक पहल है। राज्य आजीविका मिशन बड़ी संख्या में लाभार्थियों को कवर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इस मॉडल को अपना सकते हैं।

डॉ. रमेश सक्तीवेल
एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआईएटी
कवर पेज डिज़ाइन: **श्री वी जी भट्ट**

तेलंगाना को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए तेलंगाना में पोषण अभियान को लागू करने पर अभिसरण बैठक

एनआईआरडीपीआर में अभिसरण बैठक के दौरान सुश्री मीताल रूसिया, अध्यक्ष , यूनिसेफ, एचएफओ का अभिवादन करते हुए डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर

डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीजीजीपीए और संचार संसाधन इकाई (सीआरयू) टीम द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद में 18 जुलाई, 2019 को तेलंगाना राज्य में पोषण संबंधी परिणामों को प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रमुख लाइन विभागों के साथ एक उच्च-स्तरीय अभिसरण बैठक आयोजित की गई । इस बैठक में सचिवों, विभागों के प्रमुख (एचओडी) और महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिवासी कल्याण, एसईआरपी और यूनिसेफ के अधिकारी उपस्थित हुए। बैठक की अध्यक्षता एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी ने की, और प्रतिभागियों ने 2022 तक निर्धारित पोषण अभियान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लाइन विभागों, कार्यक्रमों और योजनाओं द्वारा अपेक्षित अभिसरण कार्यों पर विचार-विमर्श किए।

स्वागत टिप्पणियों के दौरान डॉ. ज्ञानमुद्रा प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सुशासन एवं नीति विश्लेषण केंद्र, एनआईआरडीपीआर ने एनआईआरडीपीआर में संचार संसाधन इकाई (सीआरयू) और इसके कार्यों के साथ-साथ पोषण अभियान, इसके घटक और विभाग 2022 तक तेलंगाना के लिए पोषण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रत्येक विभाग कैसे योगदान कर सकते है पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति प्रस्तुत किए । जीवन-चक्र दृष्टिकोण के आसपास के मुद्दों और संबंधित व्यवहारों का उपयोग करके विभिन्न विभागों की भूमिका प्रस्तुत की गई।

इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार और भागीदारों के प्रयासों का लक्ष्य 100 प्रतिशत उपलब्धि की ओर होना चाहिए। अपने प्रगतिशील प्रशासन, बुनियादी ढांचे और अच्छे स्वास्थ्य संकेतक जैसे कि संस्थागत प्रसव के उच्च प्रतिशत के साथ तेलंगाना जैसे अग्रिम राज्य को प्रत्येक बच्चे और महिला को स्वस्थ बनाने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्य 2022 तक तेलंगाना को कुपोषण मुक्त राज्य बनाना है । इसे ग्राम पंचायत स्तर पर अच्छे क्रॉस लिंकेज, पीआरआई, एसएचजी जैसी सामुदायिक संरचनाओं और अन्य स्थानीय नेताओं को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरणा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने पीआरआई प्रशिक्षण में स्वास्थ्य एवं पोषण के मुद्दों पर एक कैप्सूल को एकीकृत करने का सुझाव दिया, जिसे तेलंगाना में एक आदर्श के रूप में शुरू किया जा सकता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री एम. जगदीश्वर ने कहा, "उचित हस्तक्षेप के साथ किशोर लड़कियों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करना समय की जरूरत है।" इस बात को जारी रखते हुए, उन्होंने कुपोषण के मुद्दे को हल करने के लिए सबसे आवश्यक हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देने के लिए गुणवत्ता डेटा की आवश्यकता पर जोर दिया।

अन्य विभागों ने पोषण के क्षेत्र में जो काम किया जा रहा है उसे साझा किया । आयुक्त, जनजातीय कल्याण ने गिरी पोषाणा कार्यक्रम को लागू करने में अपने प्रयासों को साझा किया, जो इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे विभिन्न खाद्य पदार्थ आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करते हैं । आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ने जिला और मंडल स्तरों पर पीआरआई और ग्राम सचिवों की आगामी प्रशिक्षण में स्वास्थ्य और पोषण पर एक कैप्सूल को एकीकृत करने का सुझाव दिया । छोटे जीपी के साथ, पीआरआई जीपी स्तर पर स्वास्थ्य और पोषण संबंधी परिणामों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और अभिसरण के लिए नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। सीईओ, एसईआरपी, ने स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और लिंग मुद्दों पर स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं के साथ किए गए व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के बारे में जानकारी साझा की। निदेशक, स्कूल शिक्षा ने स्कूल परिसर में 13,500 एडब्ल्युसी का पता लगाने की प्रक्रिया के बारे में अद्यतन किया । उन्होंने प्री-स्कूल और प्राथमिक स्कूल शिक्षा के बीच निरंतरता में अंतर के बारे में भी चिंता जताई। उन्होंने बचपन की शिक्षा की गुणवत्ता पर आंगनवाड़ी शिक्षकों के प्रमाणन की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के लिए यूनिसेफ फील्ड कार्यालय की प्रमुख सुश्री मित्तल रूसोडिया ने बैठक के आयोजन के लिए एनआईआरडीपीआर के प्रयासों की सराहना की और रणनीति, डेटा विश्लेषण, निगरानी और एसबीसीसी में पोषण अभियान के लिए यूनिसेफ के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यवहार परिवर्तन को चलाने के लिए कार्यक्रमों में संदेश भेजने में निरंतरता महत्वपूर्ण है।

श्री जगदीश्वर, आईएएस, प्रमुख सचिव, डीडब्ल्युसीडी, श्री विजया कुमार, निदेशक, स्कूल शिक्षा, श्रीमती. नीतू प्रसाद, आयुक्त, पंचायती राज, डॉ. क्रिस्टीना जेड चोंगथू, आयुक्त आदिवासी कल्याण, श्रीमती. पसुमी बसु, सीईओ, एसईआरपी, सुश्री विजिंदिरा बोई, निदेशक, डब्ल्युसीडी, तेलंगाना, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सुश्री मितल रूसिया, प्रमुख, यूनिसेफ, सुश्री सीमा कुमार, सी४डी और सुश्री ख्याति, यूनिसेफ, हैदराबाद के पोषण विशेषज्ञ और बैठक में यूनिसेफ के अन्य विशेषज्ञों ने बैठक में भाग लिया।

पशुधन के माध्यम से बेहतर आजीविका को बढ़ावा देने पर टीओटी कार्यक्रम

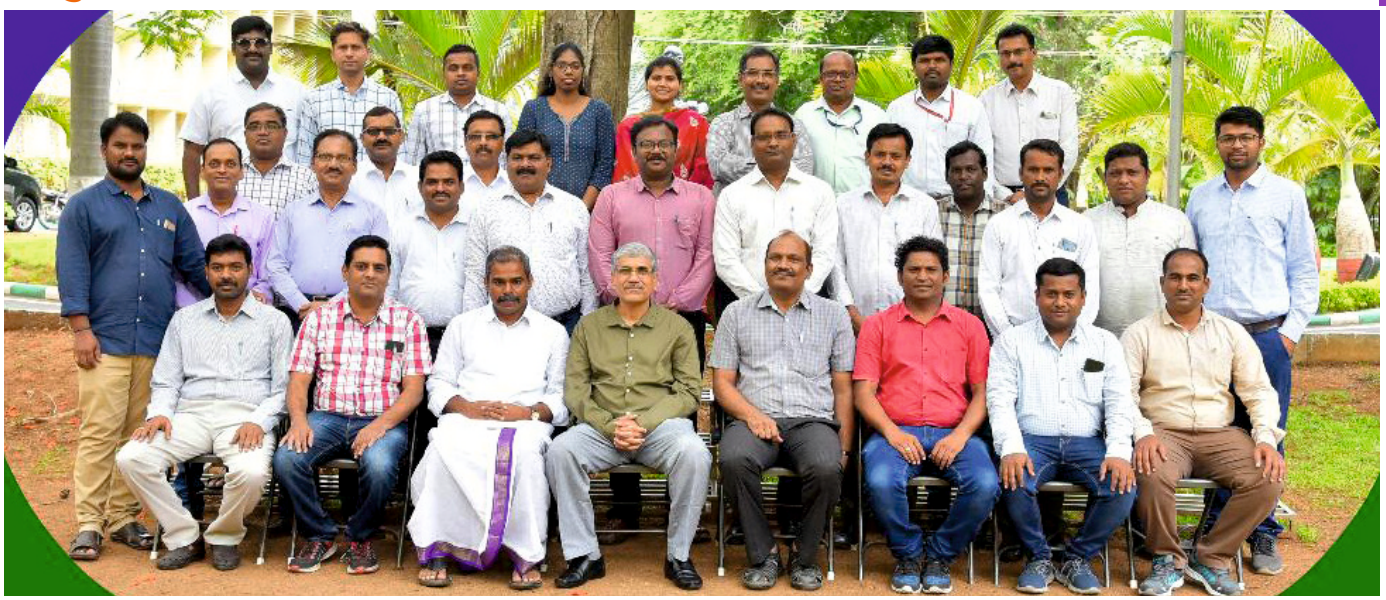

कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति, बाएं से चौथें) और डॉ. रमणा रेड्डी, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएफएल (पहली पंक्ति, बाईं ओर से पांचवें)

22 से 25 जुलाई, 2019 तक एनआईआरडीपीआर, राजेंद्रनगर, हैदराबाद में आजीविका केन्द्र (सीएफएल), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 'पशुधन के माध्यम से बेहतर आजीविका को बढ़ावा देने' पर राष्ट्र स्तर के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) रिपीट कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से छत्तीस नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से 25 लोगों ने इसमें भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकृत पांच प्रतिभागी थे, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) जिन्हें कौशल विकास, उद्यमिता और आजीविका विभाग, कर्नाटक द्वारा नामित किया गया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बारह आंतरिक व्याख्यान (आर्ट ऑफ लिविंग सहित), दो मामला अध्ययन, एक स्थानीय दौरा (पोल्ट्री अनुसंधान निदेशालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद) और मुल्कानूर महिला सहकारी डेयरी संघ, मुल्कानूर, वारंगल जिला (शहरी) का क्षेत्र शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को भारत में पशुधन खेती के वर्तमान परिदृश्य, ग्रामीण आजीविका में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया और कैसे हम पशुपालकों की मांग को ध्यान में रखते हुए पशुधन के माध्यम से छोटे धारक किसानों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं तथा भविष्य के बदलाव जो भारत में होने जा रहे हैं पर जानकारी दी गई।

पीएमजीएसवाई सड़क योजना और प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों पर पांच दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीगार्ड (दाईं ओर से चौथे) प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

ग्रामीण विकास में भूसंसूचना अनुप्रयोग केंद्र (सीगार्ड) ने 22-26 जुलाई, 2019 तक गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (जीएनएलयू), गांधीनगर में एसआआरडी, गुजरात के सहयोग से योजना और पीएमजीएसवाई सड़कों के प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर पांच दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

पहले दिन, डॉ. एम. वी. रविबाबू, एसोसिएट प्रोफेसर (सीगार्ड) और कार्यक्रम निदेशक ने पांच दिवसीय कार्यक्रम के कार्यक्रम अनुसूची और उद्देश्यों के बारे में

प्रकाश डाला । ग्रामीण सड़कों की योजना और प्रबंधन के लिए जीआईएस डेटा लेयर का विश्लेषण, भू-सूचना जैसे विषयों पर चर्चा की गई की अवधारणाएं, एसेट मैपिंग के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का विश्लेषण करना । डॉ. किरण जालम, सहायक प्रोफेसर (सीआरसीटीएन) और सह-निदेशक कार्यक्रम ने स्थानिक योजना में जीआईएस-आधारित उपकरणों का उपयोग करने के प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया । प्रतिभागियों ने मोबाइल आधारित अनुप्रयोगों का उपयोग करते हुए नजदीकी पीएमजीएसवाई सड़कों से फील्ड डेटा संग्रह द्वारा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया । प्रशिक्षण में पीएमजीएसवाई/पीडब्ल्युडी / आरआर इंजीनियरों के कुल 31 अधिकारियों ने भाग लिया। मोबाइल जीपीएस का उपयोग कर डेटा संग्रह के लिए एसआईआरडी कार्यक्रम समन्वयक, श्री धवल पारिख के साथ परिसर में एक क्षेत्र दौरा कार्यक्रम आयोजित किया गया । सभी प्रतिभागियों को टीमों में विभाजित किया गया और क्षेत्र से डेटा एकत्र करते समय विभिन्न परिसंपत्तियों, विशेष रूप से सड़कों और उनकी स्थितियों को एकत्र किया गया । प्रतिभागियों ने फील्ड स्थितियों की कल्पना कर उसका अनुभव किया।

अंतिम दिन के समापन सत्र में श्री विक्टर मैकवान, आईएएस, विशेष निदेशक, एसआईआरडी गुजरात ने अपना समापण भाषण दिया और सभी प्रतिभागियों से बातचीत की । उन्होंने विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी करते हुए बुनियादी ढांचे के विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला । उन्होंने यह भी कहा कि यह तकनीक पीएमजीएसवाई सड़कों तक सीमित नहीं है, और अन्य क्षेत्र के अधिकारियों के लिए विस्तारित की जा सकती है और क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन की आधिकारिक गतिविधियों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का सुझाव दिया । अंत में, उन्होंने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी और प्रमाण पत्र वितरित करते हुए उनसे बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्राप्त की । सभी प्रतिभागियों ने महसूस किया स्थानिक योजना के रूप में उनकी सड़क सूचना प्रणाली तैयार करने में प्रशिक्षण कार्यक्रम उपयोगी था ।

सीएफआईई ने वित्तीय साक्षरता पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया

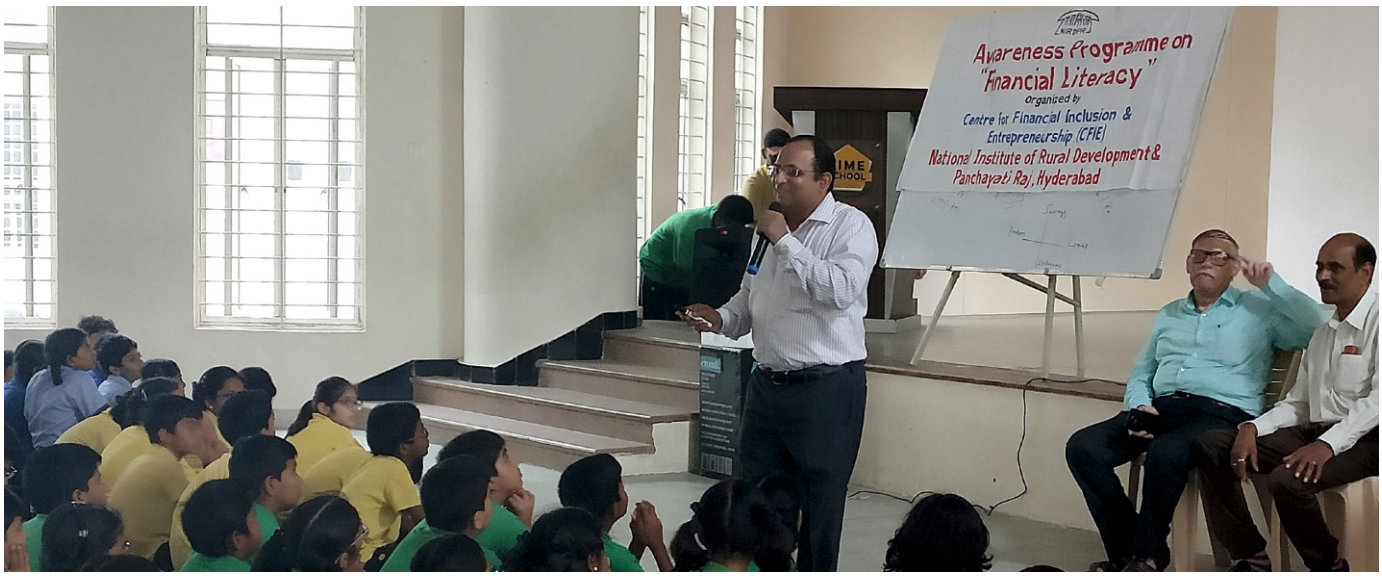

डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीएफआईई, टाईम स्कूल, बंडलागुड़ा परिसर में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए

वित्तीय समावेश और उद्यमशीलता केन्द्र (सीएफआईई) ने 06 जुलाई, 2019 को एनआरडीपीआर, भारतीय विद्या भवन (बीवीबी) में वित्तीय साक्षरता पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया और 20 जुलाई, 2019 को टाईम स्कूल, बंडलगुड़ा परिसर में, कक्षा 6 से 10 के छात्र कार्यक्रम में उपस्थित हुए । सत्र का संचालन डॉ. आर. वी. प्रसाद भारतीय स्टेट बैंक के वित्तीय साक्षरता सलाहकार, आरएसईटीआई – चिलुकुरू ने किया ।

कार्यक्रम का उद्घाटन एनआईआरडीपीआर परिसर, भारतीय विद्या भवन स्कूल के प्राचार्य श्री रवि किरण ने किया और श्रीमती अरुणा ज्योति, एक वरिष्ठ संकाय बीवीबीवी, एनआईआरडीपीआर, परिसर ने संयोजन किया । टाइम स्कूल में कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती विजया लक्ष्मी, प्रिंसिपल, टीआईएमई, बंडलागुड़ा द्वारा किया गया और बच्चों के लिए इस तरह के शिक्षाप्रद कार्यक्रमों की व्यवस्था के लिए एनआईआरडीपीआर का आभार व्यक्त किया ।

बातचीत के दौरान, डॉ. आर.वी. प्रसाद ने वित्तीय साक्षरता, बचत की आदत, क़िफायत जमा, मानव की बुनियादी जरूरतों को वित्त और बच्चों के आवश्यक बैंकिंग सुविधाओं से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझाया । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीवन में निश्चित स्तर के बाद, लोगों के लिए पैसा उपयोगी होना चाहिए, न कि इसके विपरीत। उन्होंने उल्लेख किया कि सुरक्षा, लाभ और रिटर्न के कारण बैंकों के साथ बचत करना सुरक्षित है । उन्होंने खातों के कार्ड एवं उपलब्ध ऋणों के प्रकार, योजनाओं आदि के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दी। डॉ. प्रसाद ने सभी के जीवन के शुरुआती चरण के दौरान बैंकिंग आदतों के अनेक फायदे बताए ।

समापन समारोह की अध्यक्षता डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, सीएफआईई ने की, उन्होंने छात्रों को पैसे के मूल्य को समझने के लिए एक किस्सा सुनाया । कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से समझा गया और छात्रों के साथ-साथ दोनों स्कूलों के संकाय द्वारा भी सराहा गया । उन्होंने वित्तीय समावेशन अभियान के भाग के रूप में अपने माता-पिता और पड़ोसियों के साथ प्रमुख विषयों को साझा करने का वादा किया ।

सीएफआईई की टीम, अर्थात डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रमुख, डॉ. ए. भवानी, परियोजना सलाहकार, श्री जी. अंजनेयुलु, परियोजना सलाहकार और श्रीमती सीरीशा रेड्डी, प्रशिक्षण प्रबंधक ने इन कार्यक्रमों का समन्वय किया ।

मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों का मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम

डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति, बाएं से चौथे) और डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर और प्रमुख, सीजीजी और पी ए (पहली पंक्ति, दाएँ से दूसरी) कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ

डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर और प्रमुख, सी जी जी और पी ए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायत राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दो दिवसीय 'मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम' का आयोजन जुलाई 15, 16, 2019 को एनआईआरडीपीआर में किया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, उपायुक्तों और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट आदि जैसी विभिन्न श्रेणियों के जिम्मेदारियाँ रखने वाले कुल २२ अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास, हाल ही ग्रामीण पहल के साथ-साथ विभिन्न विकास कार्यक्रमों पर अधिकारियों के ज्ञान को ताजा करना और उन्हें राज्य के जन कल्याण हेतु अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के कौशल के साथ प्रेरित करना था।

डॉ. ज्ञानमुद्रा ने औपचारिक रूप से सभी को आमंत्रित किया और दो-दिवसीय प्रशिक्षण के अवलोकन पर एक सत्र लिया और एनआईआरडीपीआर तथा इसके विभिन्न पहलुओं का संक्षिप्त परिचय दिया। डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का सार और लाभ समझाया तथा सभी से इस अवसर का उपयोग करने का अनुरोध किया।

डॉ. अमिताव मुखर्जी, पूर्व वरिष्ठ सलाहकार, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एनआरएलएम, नई दिल्ली ने ''सामाजिक पहल द्वारा भारत का बदलता स्वरूप'' पर एक सत्र लिया और प्रतिभागियों की यादो को ताजा किया । डॉ. वी. भास्कर, आईएएस (सेवानिवृत्त), ने 'प्रशासनिक पद्धति और इसकी कार्य शैली, जवाबदेही और पारदर्शिता की समझ पर एक सत्र लिया; उन्होंने विभिन्न चुनौतियों पर जोर दिया जिसका सामना कार्यकाल के दौरान कोई भी कर सकता है और उन्हें अंतर्दृष्टि दी कि कैसे इन समस्याओं का अत्यंत प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ समाधान किया जा सकता है। डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर और प्रमुख, सी जी जी और पी ए ने ग्रामीण विकास - वर्तमान पहल पर एक सत्र लिया। भारत सरकार की विभिन्न हालिया पहलों को कवर किया गया जिसमें पोषण अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, डीएवाई-एनआरएलएम, आयुष्मान भारत आदि शामिल हैं और इन कल्याणकारी कार्यक्रमों के निर्वहन में जिला-स्तरीय अधिकारियों की भूमिका पर जोर दिया गया। सभी प्रतिभागियों को ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) ले जाया गया, जिसमें आरटीपी द्वारा ग्रामीण लोगों का क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में उत्थान करने की विभिन्न पहलों के लिए एक्सपोजर दिया गया, जैसे कि सस्ती निर्माण तकनीक, ग्रामीण रोजगार सृजन और आजीविका।

श्री सोमेश कुमार, आईएएस, विशेष मुख्य सचिव, राजस्व (सीटी एवं एक्स) ने नवाचारों और सुधारों के माध्यम से जिला प्रशासन में सुधार पर एक प्रेरक सत्र लिया। उन्होंने सभी अधिकारियों को वस्तुओं को नया करने और सुधारने के आधार के रूप में संकट के मुद्दों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। श्री जयेश रंजन, आईएएस, ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक गतिशीलता के महत्व पर एक सत्र लिया। वर्तमान में यूनिसेफ-दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सुश्री सुमिता डावरा, आईएएस ने शासन में बाल हितैषी हस्तक्षेप पर एक सत्र लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन सुश्री सुमिता डावरा, आईएएस द्वारा समापन सत्र के साथ किया गया और सभी प्रतिभागियों को पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र दिए गए। डॉ. ज्ञानमुद्रा ने सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि इस प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारी अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में मदद करेगी।

पीएमजीएसवाई सड़कों की योजना और प्रबंधन के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

पीएमजीएसवाई सड़कों की योजना और प्रबंधन के लिए भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों पर 15-19 जुलाई, २०१९ के दौरान एसआईआरडी, हिमाचल प्रदेश में एक ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया । कार्यक्रम को एनआरआरडीए, एमओआरडी, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया।

हिमाचल प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के कुल 24 इंजीनियरों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया।

प्रारंभिक सत्र में, प्रशिक्षण, निगरानी, मूल्यांकन और ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की बुनियादी अवधारणाओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा, सत्र में एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी और विभिन्न खुले स्रोत जीआईएस टूल और मोबाइल मैपिंग ऐप को पेश किया गया । प्रयोगशाला सत्रों के दौरान सड़क सुविधाओं से संबंधित विभिन्न जीआईएस संचालन, डेटा निर्माण और संपादन प्रक्रियाएं प्रदर्शित की गईं ।

प्रदर्शनी दौरा और कक्षाओं के दौरान प्रतिभागियों को पीएमजीएसवाई राष्ट्रीय जीआईएस पोर्टल, भू स्थानिक ग्रामीण सड़क सूचना प्रणाली (जीआरआरआईएस) से परिचित कराया गया।

कुल मिलाकर, तीन सॉफ्टवेयर टूल और मोबाइल ऐप जैसे कि क्यूजीआईएस, गूगल अर्थ और ओस्मांड का प्रयोग सुलभ शिक्षा अनुभव के लिए किया गया।

क्षेत्र दौरा

प्रशिक्षण के चौथे दिन आधे दिन की क्षेत्र दौरे का आयोजन किया गया ताकि पास के पीएमजीएसवाई मार्ग पर हिमाचल प्रदेश के इलाके की स्थितियों में मोबाइल मैपिंग एप्लिकेशन को ट्रैक और परीक्षण कर सके । 'सदोडा से क्यारकोट (मोहनपुर) लिंक रोड' तक का तीन किलो मीटर ट्रैक किया गया । बाद में, मोबाइल में निहित डेटा को ईमेल के माध्यम से निर्यात किया गया और अगले दिन कक्षा में अभ्यास के दौरान पीसी पर डाउनलोड किया गया। क्यूजीआईएस और गूगल अर्थ में डेटा का ओवरलेयिंग किया गया । सभी प्रतिभागी योजना और निगरानी के उद्देश्यों के लिए डेटा की गुणवत्ता से संतुष्ट थे।

उसी दिन के दूसरे भाग में, जीआईएस से संबंधित सभी कार्यों के लिए राज्य सरकार के एक नोडल केंद्र, आर्यभट्ट भू-स्थानिक और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एजीआईएसएसी), शिमला के लिए संपर्क दौरा की गई, ताकि वैज्ञानिकों के साथ बातचीत और संपर्क किया जा सके। प्रतिभागियों ने बातचीत की और एजीआईएसएसी से जुड़ी विशेष और प्रमुख जीआईएस परियोजनाओं में पीएमजीएसवाई और पीडब्ल्युडी सड़क परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया गया।

गूगल ड्राइव के माध्यम से पाठ्यक्रम सामग्री प्रदान की गई । प्रतिभागियों को कई ऑनलाइन जानकारी प्लेटफार्मों और यू टयूब चैनल (जीआईएस-संबंधित सामग्री के लिए समर्पित रूप से बनाया गया) से परिचित कराया गया।

प्रतिक्रिया और मूल्यांकन

समापन के दौरान, पीएमजीएसवाई योजना में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले पीडब्ल्युडी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के सभी पहलुओं और आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा की। प्रतिभागियों ने कहा कि वे कार्यालय / साइट से सीधे सभी जीआईएस परिचालन का प्रबंधन करने में सक्षम होंगे और जीआईएस से संबंधित कार्यों के लिए राज्य मुख्यालय और एजीआईएसएसी में आने की आवश्यकता कम हो जाएगी।

प्रतिभागियों ने एसआईआरडी छात्रावास के नवीकरण और रखरखाव की आवश्यकता का संकेत दिया, जिसे एसआईआरडी अधिकारियों ने विधिवत रूप से नोट किया । प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल पर प्रशिक्षण का ऑनलाइन फीडबैक लिया गया।

श्री एच.के. सोलंकी, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, सीगार्ड, एनआईआरडीपीआर ने पाठ्यक्रम का संयोजन किया। एसआईआरडी की ओर से हिमाचल प्रदेश के एसएच सर्वेश कुमार, मूल संकाय सदस्य, एसआईआरडी ने पाठ्यक्रम का संयोजन किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ श्री एच. के. सोलंकी, वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर, सीगार्ड (दाईं ओर से 7 वें)

ग्रामीण विकास व्यवसायियों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण क्रियाविधि पर एनआईआरडीपीआर ऑफ-कैंपस प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, सीएचआरडी (पहली पंक्ति, बाएं से पांचवें) और डॉ. ओपी पांडे, अपर निदेशक, एसआईआरडी, लखनऊ (पहली पंक्ति, बाएं छठें)

मानव संसाधन विकास केन्द्र ने 27-31 मई, 2019 के दौरान दीन दयाल उप्पाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान क्रियाविधि और तकनीकों पर एक ऑफ-कैम्पस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया । यह कार्यक्रम पिछले साल के सामाजिक विज्ञान अनुसंधान क्रियाविधि और तकनीकों के कार्यक्रम के प्रतिभागियों द्वारा दिए गए फीडबैक और मांग के आधार पर डिजाइन और विकसित किया गया, जो 28- 31, अगस्त 2018 के दौरान एसआईआरडी, लखनऊ में आयोजित किया गया । कार्यक्रम को प्रतिभागियों ने सराहा और विशेष रूप से जिला ग्रामीण विकास संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के अधिकारियों के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण क्रियाविधि की बुनियादी बातों पर एक कार्यक्रम की मांग की गई । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की कल्पना की गई और ग्रामीण विकास के संस्थानों में काम करने वाले संकायों की क्षमता का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया । प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य हैं:

(1) विकास के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण क्रियाविधि के ज्ञान पर प्रतिभागियों को उन्मुख करना

(2) प्रतिभागियों को प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण विधियों को सीखने में सक्षम बनाना

(3) प्रतिभागियों को अनुसंधान करने के लिए अनुसंधान क्रियाविधि और सांख्यिकीय तरीकों की मूल बातें सिखाना और

(4) अनुसंधान डिजाइन तैयार करने के लिए प्रतिभागियों को कौशल से सुसज्जित करना ।

इस कार्यक्रम में जिला प्रशिक्षण अधिकारी, विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी, वरिष्ठ प्रशिक्षक, जिला ग्रामीण विकास संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के प्रशिक्षक के रुप में कार्य कर रहे कुल 3 1 प्रतिभागियों ने भाग लिया । एनआईआरडीपीआर के संकाय के अलावा, प्रख्यात स्त्रोत व्यक्ति प्रो बी के बाजपेयी, निदेशक, और डॉ. अनिमेष रॉय, गिरि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, लखनऊ, प्रो. मधुलिका दुबे, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ और डॉ. विवेक कुमार, जिला प्रशिक्षण अधिकारी को सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की अवधारणाओं पर सत्र लेने के लिए आमंत्रित किया गया । कार्यक्रम एनआईआरडीपीआर पर एक लघु फिल्म के साथ शुरू हुआ ।

कार्यक्रम के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, सामग्री और उसके सत्रों को इस तरह से संरचित किया गया कि इसमें अनुसंधान और प्रशिक्षण क्रियाविधि की मूल अवधारणाओं को कवर किया गया । कवर किए गए कार्यक्रम की सामग्री प्रशिक्षकों के लिए अनुसंधान पद्धति, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की अवधारणा, वयस्क सीखने के सिद्धांत, शोध समस्या की पहचान और परिभाषित करना, अनुसंधान प्रस्ताव लिखना, नमूना और नमूना पद्धति, डेटा विश्लेषण: वर्णनात्मक और ह्रासमान आँकड़े, उपकरण हैं अनुसंधान, डेटा विश्लेषण के लिए एसपीएसएस का उपयोग करने के लिए कौशल, समूह अभ्यास और पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रस्तुति और इनपुट के बाद अनुसंधान डिजाइन, प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण, प्रशिक्षण की जरूरत की पहचान, प्रशिक्षण कार्यक्रम के डिजाइन, प्रशिक्षण विधियों, और प्रशिक्षण कार्यक्रम के निर्माण पर अभ्यास। इसके अलावा, प्रतिभागियों के लिए आधे दिन की स्थानीय दौरे का भी व्यवस्था की गई । प्रशिक्षण में उपयोग की गई प्रशिक्षण क्रियाविधि कार्यक्रम की सामग्री के अनुसार थी। अधिकतर, प्रतिभागी-उन्मुख जैसे कि व्याख्यान-सह चर्चा, समूह अभ्यास, प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुतियाँ और अनुभवों ने कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बना दिया ।

कार्यक्रम के अंत में, पाठ्यक्रम टीम ने डॉ. डी. सी. उपाध्याय, अपर निदेशक, डीडीयूएसआईआरडी, लखनऊ को पाठ्यक्रम और प्राप्त शिक्षा के बारे में प्रतिभागियों के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। कार्यक्रम से प्रतिभागियों ने अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त किया और भविष्य में इस विषय पर और अधिक कार्यक्रमों की मांग की गई। अंत में, इस कार्यक्रम का मूल्यांकन प्रतिभागियों ने किया और बताया कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक प्रशिक्षणार्थी के तीनों डोमेन में सुधार हुआ है, अर्थात् ज्ञान (94 प्रतिशत), कौशल (88 प्रतिशत) और दृष्टिकोण (90)। कार्यक्रम की कुल प्रभावशीलता 87 प्रतिशत रही। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए, अधिकांश प्रतिभागियों ने व्यक्त किया कि प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य के संचालन में उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग नहीं किया जाता है। पाठ्यक्रम टीम ने सभी प्रतिभागियों को एनआईआरडीपीआर के अनुसंधान निधि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है जो विशेष रूप से ईटीसी / डीआईआरडी / आरआईआरडी के संकाय के लिए छोटे स्तर के अनुसंधान कार्य को करने के लिए रखा गया है। पाठ्यक्रम की टीम भी अनुसंधान प्रस्तावों को तैयार करने में सभी संकायों की मदद के लिए आगे आई है। कई प्रतिभागियों ने अनुसंधान प्रस्तावों को विकसित करने में अपनी रुचि दिखाई है।

कार्यक्रम का संयोजन डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, मानव संसाधन विकास केंद्र, डॉ. टी. विजय कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समता एवं सामाजिक विकास केंद्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया। डॉ. डी.सी. उपाध्याय, अपर निदेशक, डीडीयूएसआईआरडी, लखनऊ इस कार्यक्रम के लिए स्थानीय संयोजक थे।

बेहतर सेवा वितरण के लिए ई-शासन हेतु रणनीतियों पर क्षेत्रीय टीओटी कार्यक्रम

टीओटी के प्रतिभागियों के साथ डॉ. के. प्रभाकर, सहायक प्रोफेसर, सीजीजीपीए (पहली पंक्ति, बाईं ओर से तीसरे)

सु-शासन और नीति विश्लेषण केन्द्र (सीजीजीपीए) द्वारा 2-4, जुलाई 2019 के दौरान एसआईआरडीपीआर, कारफेक्टर, जोरेथांग, सिक्किम में 'बेहतर सेवा वितरण के लिए ई-शासन हेतु रणनीतियों' पर एक क्षेत्रीय टीओटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

बेहतर सेवा वितरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए ई-शासन की रणनीतियाँ निम्नलिखित उद्देश्यों को संबोधित करती हैं:

- सेवा वितरण में ई-शासन की आवश्यकता और अवधारणा पर चर्चा करना
- ई-शासन पहल के सर्वोत्तम अभ्यासों से अनुमान लगाना
- बेहतर प्रशासन लक्ष्य उपलब्धियों के लिए ई-शासन की भूमिका के बारे में ज्ञान और कौशल उत्पन्न करना
- बेहतर सेवा वितरण के लिए ई-शासन पहल को प्रतिभागियों द्वारा अपनाना

प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नलिखित चार मॉड्यूल को कवर करने के पर प्रकाश डालता है:

मॉड्यूल 1 : सुशासन: एक अनुशासनात्मक परिवर्तनकारी अवधारणा

मॉड्यूल 2: ई- शासन: समकालीन समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी

मॉड्यूल 3: ई-शासन पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर सेवा वितरण जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए अग्रणी है

मॉड्यूल 4: राज्य प्रदर्शन के अनुभवजन्य कारकों के रूप में ई-शासन के लिए रणनीतियाँ

प्रशिक्षण कार्यक्रम की सामग्री को व्याख्यान-सह चर्चा के विवेकपूर्ण मिश्रण के माध्यम से वितरित किया गया; भूमिका निभाना; बहस; प्रदर्शनी दौरा, समूह अभ्यास; नकली पंचायतें; समूहों में प्रस्तुति, व्यक्तिगत और रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण।

विभिन्न विषयों को कवर करने के लिए कार्यक्रम की योजना बनाई गई, जैसे कि भारत में ई-शासन की पहलुएँ, सुशासन -भारतीय दृष्टिकोण और ग्रामीण विकास में ई- शासन का महत्व, एनआईसी सिक्किम द्वारा ई- शासन रणनीतियाँ, ई- शासन, कृषि और ग्रामीण विकास में आईसीटी, पंच तंत्रा ग्राम पंचायत ऑनलाइन प्रणाली – जिला परिषद् मैसूरु- कर्नाटक का मामला, आधार सक्षम सार्वजनिक वितरण प्रणाली आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा सफल ई-शासन सेवा वितरण पहल, मनरेगा कार्यक्रम में शासन - विशेष रूप से सिक्किम राज्य पर, बेहतर सेवा वितरण के लिए ई- शासन की रणनीति- एनआईआरडीपीआर अनुभव (ई-ऑफिस) और स्मार्ट मीटिंग सिस्टम (एसएमएस), ऑनलाइन धान प्रबंधन प्रणाली - तेलंगाना राज्य नागरिक आपूर्ति द्वारा ई-शासन पहल और चर्चा और समूह कार्य गतिविधियों के लिए सफल मामले।

तीसरे दिन, प्रतिभागियों को 25- लुंगचोक कामेरी जीपीयू में जीपी अध्यक्ष और सदस्यों के साथ बातचीत करने के लिए ले जाया गया और सभी प्रतिभागियों ने पंचायत पीआरआई और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ ई-शासन टीओटी ज्ञान और अनुभवों पर प्राप्त जानकारी साझा की । प्रतिभागियों ने विभिन्न राज्यों आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा एईपीडीएस, कर्नाटक राज्य द्वारा पंच तंत्र के रूप में कुछ अच्छे ई-शासन पहलुओं और प्रथाओं का सुझाव दिया, ताकि सिक्किम राज्य में ग्राम पंचायत सदस्य बेहतर ई-शासन मॉडल के रूप में दोहराये।

अंतिम दिन, प्रतिभागियों को चार समूहों में विभाजित किया गया और प्रत्येक समूह ने टीओटी और क्षेत्र दौरा सीख पर एक प्रस्तुति दी । प्रत्येक टीम ने दो अलग-अलग समूह की गतिविधियाँ और प्रस्तुतियाँ बनाईं, अर्थात्, पहली प्रस्तुति किसी पहचानी हुई, प्रासंगिक और टीओटी से अच्छी ई शासन से सीख और सिक्किम राज्य में इसे कैसे दोहराया जा सकता है पर एसडब्ल्युओटी विश्लेषण का प्रयास पर थी और दूसरी प्रस्तुति क्षेत्र दौरे पर थी अर्थात, जीपी और पीआरआई और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान प्रत्येक समूह ने विज़िट किए गए जीपी में ई-शासन अंतराल की पहचान की और जीपी के दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए टीओटी सीख से उपयुक्त ई-शासन पहल का सुझाव दिया।

कार्यक्रम में विभिन्न पृष्ठभूमि के कुल ३२ लोगों ने भाग लिया, डॉ. प्रभाकर, सहायक प्रोफेसर, सु-शासन और नीति विश्लेषण केन्द्र (सीजीजीपीए) ने ऑफ कैंपस क्षेत्रीय टीओटी कार्यक्रम का आयोजन किया।

एमजीएनआरईजीएस और डे - एनआरएलएम पर प्रशिक्षण कार्यक्रम : सीबीओ भागीदारी के साथ श्रम गतिशीलता और सामाजिक लेखापरीक्षा को बढ़ावा देना

कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडब्ल्युई (पहली पंक्ति, बाएं से 5 वें), डॉ. डी. सुरेश बाबू, एसोसिएट प्रोफेसर, सीसीसी और डीएमडीएम (पहली पंक्ति, बाएं से 4 वें), डॉ. नीरज मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, सीडब्ल्युई (प्रथम पंक्ति, दाईं ओर से पहला) और डॉ. पी. अनुराधा, सहायक प्रोफेसर, सीडब्ल्युई (पहली पंक्ति, दाईं ओर से 5 वीं)

मजदूरी रोजगार केंद्र, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने 'एमजीएनआरईजीएस और डे – एनआरएलएम: सीबीओ की भागीदारी के साथ श्रम गतिशीलता और सामाजिक लेखापरीक्षा को बढ़ावा देना' पर 8-12 जुलाई, 2019 से एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।।

14 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल से कुल 29 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया । प्रतिभागियों में राज्य ग्रामीण विकास, पंचायती राज और एमजीएनआरईजीएस के साथ काम करने वाले अन्य लाइन विभागों के वरिष्ठ और मध्यम स्तर के अधिकारी थे।

कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्य:

- आईपीपीई प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी और श्रम बजट, जीपीडीपी, सामाजिक लेखापरीक्षा और रोज़गार दिवस की तैयारी के लिए महिला एसएचजी को जुटाने में प्रतिभागियों की क्षमता का निर्माण करना

- एमजीएनआरईजीएस के माध्यम से स्थायी आजीविका के बारे में जागरूकता सृजन करना

- श्रम बजट की तैयारी और सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया में स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी के महत्व की पहचान करना

- एमजीएनआरईजीएस और एनआरएलएम के बीच अभिसरण में सफल मामलों / सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रतिभागियों को परिचित करना

कार्यक्रम की सामग्री:

- मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति

- कमजोर महिलाओं की मांग और उन्हें सशक्त बनाने के लिए रोज़गार दिवस

- एमजीएनआरईजीएस और डे-एनआरएलएम के बीच अभिसरण

- महिलाओं की भागीदारी पर सर्वोत्तम अभ्यास

कार्यक्रम के भाग के रूप में प्रतिभागियों के लिए क्षेत्र अध्ययन आयोजित किया गया । उन्होंने इब्राहिमपुर मॉडल गांव, सिद्दीपेट मंडल, मेदक जिले का दौरा किया । मॉडल गांव द्वारा सृजन किया गया प्रभाव एमजीएनआरईजीएस के तहत रोजगार प्रदान करके मजदूरी मांगकर्ताओं की आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर रहा है जो कि लाइन-विभागों के साथ अभिसरण द्वारा जल संचयन संरचनाओं और वृक्षारोपण कार्यों के माध्यम से भूजल पुनर्भरण कार्य करना है । गाँव में एसएचजी सदस्य एमजीएनआरईजीएस के साथ अभिसरण में विभिन्न अर्ध-कुशल या कुशल कार्यों में भाग ले रहे हैं । दिलचस्प की बात यह है कि इब्राहिमपुर को 2015 में तेलंगाना का पहला मच्छर मुक्त गाँव भी घोषित किया गया ।

प्रतिभागियों ने अपने विचार व्यक्त किए कि वे क्षेत्र दौरे से संतुष्ट हैं; यह दौरा उन्हें मुद्दों से निपटने में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में और इब्राहिमपुर जैसे मॉडल गांव का निर्माण करके चीजों को कैसे प्रबंधित किया जा सकता है को समझने में मदद की ।

कार्यक्रम का संयोजन डॉ. पी. अनुराधा, सहायक प्रोफेसर, सीडब्ल्युई और डॉ. ज्योतिस सत्यपालन, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडब्ल्युई और डॉ. नीरज मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, सीडब्ल्युई, एनआईआरडीपीआर द्वारा किया गया ।

कृषि और एमएसएमई क्षेत्रों में ऋण प्रबंधन पर बैंकरों के लिए कार्यक्रम

कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति, बाएं से 5 वां स्थान) और डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएफआईई (पहली पंक्ति, बाएं से तीसरा स्थान)

एमएसएमई क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों में इसका योगदान प्रमुख है। इस क्षेत्र में वृद्धि से भारत में बेरोजगारी की समस्या कम होने की संभावना है । कृषि क्षेत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं, वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। कृषि क्षेत्र जबरदस्त आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रहा है जो बैंक अधिकारियों द्वारा मौजूदा ज्ञान को अद्यतन करने के लिए कहता है । इसलिए, इन दोनों क्षेत्रों का वित्तपोषण देश के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है । इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, सीएफआईई ने एसएमई और कृषि ऋण अधिकारियों, ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंक शाखाओं के प्रबंधकों, नव भर्ती किए गए बैंक अधिकारियों, पदोन्नत अधिकारी, ग्रामीण ऋण / एमएसएमई ऋण पोर्टफोलियो की निगरानी और पालन करने वाले अधिकारी, जोखिम प्रबंधन विभाग के अधिकारी आदि के मूल्यांकन कौशल को बढ़ाने के लिए 'कषि और एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रबंधन' पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया । उक्त ऑफ-कैम्पस में प्रशिक्षण कार्यक्रम को 22-26 जुलाई, 2019 को एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में आयोजित किया गया । कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएफआईई ने प्रतिभागियों का स्वागत किया, कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया और इसके उद्देश्यों को बताया ।

क्षेत्र प्रदर्शनी दौरे

व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने और प्रतिभागियों को कक्षा में प्राप्त शिक्षा को मजबूत करने में मदद करने के लिए, निम्नलिखित क्षेत्र दौरे आयोजित किए गए।

(क) ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी), एनआईआरडीपीआर: प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन, प्रतिभागियों को एनआईआरडीपीआर परिसर में स्थित ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी) ले जाया गया। श्री एमडी खान, वरिष्ठ सलाहकार, नवाचार और उपयुक्त प्रौद्योगिकी केंद्र, ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। उन्होंने आरटीपी के बारे में उन्हें समझाया और मितव्ययी नवाचारों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने और ग्रामीण उद्यमियों की इकाई स्थापित करने, कौशल बनाने और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करने के बारे में बताया। उन्होंने जीवन के सभी पहलुओं जैसे क्षमता निर्माण, ग्रामीण रोजगार सृजन, आजीविका, आदि में ग्रामीण लोगों के उत्थान में आरटीपी द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में भी चर्चा की। बाद में, प्रतिभागियों ने व्यावहारिक पहलुओं को जानने के लिए विभिन्न स्टालों का दौरा किया, जिसमें ईको फ्रेंडली बिल्डिंग ब्लॉक्स सामग्री, वर्मी-कम्पोस्ट यूनिट, अपशिष्ट पेपर रीसाइक्लिंग यूनिट, लीफ प्लेट मेकिंग, आदि बनाना शामिल था।

(ख) पौल्ट्री अनुसंधान निदेशालय (डीपीआर): कार्यक्रम के दूसरे दिन (23 जुलाई, 2019) प्रतिभागियों को डीपीआर, राजेंद्रनगर, हैदराबाद ले जाया गया। डॉ. यू. राजकुमार, प्रधान वैज्ञानिक-जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, ने एक लघु वीडियो फिल्म की मदद से बैंकर-प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान की गतिविधियों के बारे में बताया और उनके विशिष्ट प्रश्नों का स्पष्टीकरण दिया। प्रतिभागियों ने संस्थान के अद्वितीय हस्तक्षेप की सराहना की जैसे कि पिछवाड़े में मुर्गीपालन (पक्षियों के प्रकार: वनराज और ग्रामप्रिया), जो ग्रामीण आजीविका को पूरक आय प्रदान करने में मदद करते रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों को संस्थान से जुड़ी एक छोटी वाणिज्यिक मुर्गीपालन इकाई का दौरा करने का अवसर मिला जहां वे पक्षियों को देख सके और उनकी गतिविधियों की व्यापक जानकारी के लिए तकनीकी कर्मचारियों के साथ बातचीत कर सके।

(ग) प्रशिक्षण कार्यक्रम के चौथ दिन को, प्रतिभागियों को श्री वेंकटेश्वर रेड्डी, भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त एजीएम द्वारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के वेलदुर्ती के समीप स्थापित खेत पर ले जाया गया। 10 एकड़ शुष्क भूमि में खेत को स्थापित किया गया है। खेत की खास बात यह है कि श्रीशैलम जलाशय से एक बैक वाटर कैनाल हैंद्री नीवा सुरजला श्रवन्ति (एचएनएसएस) से पानी को लिफ्ट सिंचाई के माध्यम से खेत में डाला जाता है। खेत में एक करोड़ लीटर की कुल क्षमता वाले दो खेत तालाब भी हैं और इन तालाबों के लिए पानी का स्रोत वर्षा जल संचयन है और जल को एचएनएसएस नहर से लिफ्ट और पंप किया जाता है। खेत में एक एकड़ में बना पॉली हाउस भी है। श्री रेड्डी एक ही खेत में १० जानवरों की डेयरी इकाई बनाकर मिश्रित खेती का अभ्यास कर रहे हैं। उस एकड़ भूमि में वे नैपियर घास भी उगा रहे हैं जिसे दुधारू पशुओं के लिए चारे के रूप में उपयोग की जाती है।

कार्यक्रम की सामग्री

- एमएसएमई और कृषि का वित्तपोषण: स्थिति और अवलोकन तथा प्राथमिकता क्षेत्र उधार मानदंड
- सूक्ष्म वित्त और एसएचजी बैंक संयोजन। कवरेज बढ़ाने के तरीके और साधन
- मामला अध्ययन के साथ वित्तीय साधनों का उपयोग करते हुए कृषि-व्यवसाय परियोजनाओं का ऋण मूल्यांकन
- मामला अध्ययन के साथ डेयरी और पौल्ट्री परियोजनाओं का वित्तपोषण
- मुद्रा ऋण के लिए विशेष संदर्भ के साथ एसएमई इकाइयों का ऋण मूल्यांकन
- कृषि वित्त में उभरते क्षेत्र - कृषि वित्त / अनुबंध खेती में संरचित वित्तपोषण मॉडल - आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला प्रबंधन
- बागवानी परियोजनाएं - फल और सब्जियां
- कृषि और संबद्ध गतिविधियों में जोखिम प्रबंधन
- मामला अध्ययन के साथ एनपीए और वसूली प्रबंधन

कार्यक्रम में केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के आठ अधिकारियों ने भाग लिया।

सीएफआईई के आंतरिक संकाय सदस्य और चयनित अतिथि संकाय, जो विषय विशेषज्ञ -सह-अभ्यासकर्ता हैं कार्यक्रम के लिए योगदान दिए हैं।

कार्यक्रम, अवधि और प्रतिभागियों के अपेक्षाओं के व्यापक और विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण क्रियाविधि की एक श्रृंखला, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, का उपयोग किया गया।

- व्याख्यान और प्रतिक्रिया सत्र (पीपीटी)
- विभिन्न विषयों पर मामला अध्ययन
- वीडियो क्लिप और चर्चा
- क्विज़ सहित व्यक्तिगत और समूह गतिविधियाँ / अभ्यास
- मुर्गीपालन (संस्थागत दौरा) और सिंचाई प्रणाली आदि का क्षेत्र दौरा / प्रदर्शन
- पुनर्कथन सत्र

प्रतिक्रिया और मूल्यांकन

प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया, जो कार्यक्रम का मूल्यांकन करने और प्रशिक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल का उपयोग करके एकत्र किया गया।

प्रतिभागियों से प्राप्त मौखिक और लिखित प्रतिक्रिया के अनुसार कार्यक्रम सफल रहा। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सफलता का श्रेय कक्षा सत्रों और क्षेत्र दौरा और सावधानीपूर्वक कार्यक्रम निष्पादन के अच्छे मिश्रण के साथ प्रभावी कार्यक्रम-डिजाइन के अलावा शांत प्रशिक्षण परिवेश, स्वच्छ वातावरण और बहुत अच्छी संरचनात्मक सुविधाओं को दिया।

डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर और केन्द्र प्रमुख-सीएफआईई के समग्र मार्गदर्शन के तहत, कार्यक्रम को सीएफआईई के परियोजना परामर्शक श्री गंगनेनी अंजनेयुलु द्वारा संयोजित किया गया।

पुस्तकालय व्याख्यान : टेबल-नमक के अज्ञात खतरों का खुलासा

टेबल नमक के दुष्प्रभाव पर व्याख्यान देते हुए डॉ. सुरेन्द्र रेड्डी नेरवटला

अमेरिका के ओहियो के प्रमुख सर्जन डॉ. सुरेंदर रेड्डी नेरवटला ने मानव शरीर पर टेबल-नमक के दुष्प्रभाव पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में व्याख्यान दिया। उन्होंने उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद से स्नातक किया है।

एनआईआरडीपीआर स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी डॉ. जावेद खान ने उनका स्वागत किया। श्री रेड्डी ने खुलासा किया कि दिल के मुद्दों का मुख्य कारण उच्च रक्तचाप है, टेबल नमक का सेवन करने के कारण होता है। दूसरा कारण तंबाकू का सेवन और तीसरा उच्च ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना है। उन्होंने एक शोध पर ध्यान दिलाया जिसमें संकेत दिया गया कि दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में दिल के मुद्दों का मुख्य कारण टेबल-नमक की अत्यधिक खपत है।

"टेबल-नमक के बजाय, एक समान स्वाद प्राप्त करने के लिए इमली, अदरक, लहसुन और धनिया का उपयोग किया जा सकता है", श्री रेड्डी ने कहा। उन्होंने कहा कि जो लोग नमक का सेवन बंद कर देते हैं, वे दो सप्ताह में दो किलोग्राम वजन कम कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे टेबल नमक का सेवन छोड़ देते हैं, तो रक्तचाप के लिए दवा लेना बंद कर सकते हैं। अध्ययन में पाया गया कि प्रतिभागी खुश थे, कम उदास थे और एनाल्जेसिक पर कम निर्भर थे। डॉ. रेड्डी ने कहा कि नमक शरीर में पानी को बनाए रखता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। डॉ. रेड्डी ने यूएसए में एक आदिवासी जनजाति के बारे में टिप्पणी की, जो अपने पूरे जीवन में कभी भी नमक का सेवन नहीं करते हैं। उनका ब्लड-प्रेशर 80/60 रहता है।

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने टेबल-नमक की वजह से होने वाली बीमारियों पर आंख खोलने वाले व्याख्यान के लिए डॉ. सुरेंदर रेड्डी को धन्यवाद दिया। श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप-महानिदेशक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रही।

-सीडीसी पहल

भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

संपादक : डॉ. के पापम्मा
सहायक संपादक: कृष्णा राज
के.एस. विक्ट र पॉल

एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
NIRDPR

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका